

संपादकीय : मुर्शिदाबाद की 'नई बाबरी' — आस्था, राजनीति और पारदर्शिता का सबसे बड़ा इम्तिहान

संपादकीय ।

मुर्शिदाबाद के रेहिनगर-बेलडांगा क्षेत्र में हाल ही में रखी गई “बाबरी-शैली मस्जिद” की नींव ने पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरे देश में नई बहसें जगा दी हैं। घटना जितनी धार्मिक-भावनात्मक लगती है, उतनी ही राजनीतिक और सामाजिक प्रश्नों से भरी भी है। दिलचस्प यह है कि मस्जिद की नींव वहां रखी गई, जहाँ न कोई पुरानी संरचना थी और न किसी विवाद का इतिहास—फिर भी यह कदम प्रतीकात्मक राजनीति की एक अत्यंत प्रभावशाली चाल बन गया है।

सबसे पहले बात स्थान की। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार यह परियोजना लगभग 20 से 25 बीघा भूमि पर प्रस्तावित है—यानी लगभग 6 से 8 एकड़ के विशाल क्षेत्र में एक ऐसा धार्मिक-सामाजिक परिसर विकसित करने का दावा है, जिसमें मस्जिद के साथ कॉलेज, अस्पताल और एक अतिथि-गृह बनाने की योजना बताई जाती है। यानी इसे एक साधारण इबादतगाह नहीं, बल्कि एक सामाजिक संस्थान की तरह पेश किया जा रहा है। परंतु इतनी बड़ी परियोजना में सबसे महत्वपूर्ण सवाल है—क्या भूमि वाजिब कागज़ात के साथ, नियामक अनुमति और सार्वजनिक पारदर्शिता के तहत खरीदी गई? इन सवालों का उत्तर अब तक अस्पष्ट है।

दूसरा पहलू—चंदा। आयोजन के बाद डोनेशन बॉक्स और डिजिटल भुगतान के ज़रिये भारी मात्रा में धन जुटने की खबरें सामने आईं। प्रारंभिक दावों में यह राशि 1.3 करोड़ बताई गई, जबकि बाद की घोषणाओं में यह आंकड़ा 2.4 करोड़ तक पहुँचने का दावा किया गया। लेकिन अब तक न तो बैंक विवरण सार्वजनिक हुए हैं, न आधिकारिक ऑडिट। सवाल यह नहीं कि लोग दान क्यों दे रहे हैं—सवाल यह है कि क्या ऐसे संवेदनशील प्रकल्प में धन का पूरा लेखा-जोखा जनता के सामने रखा जा रहा है? और यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि आयोजकों ने स्वयं अनुमानित खर्च 300 करोड़ रुपए तक होने का दावा किया है। 300 करोड़ की परियोजना के लिए पारदर्शिता सिर्फ ज़रूरी नहीं—अनिवार्य है।

तीसरा पहलू—राजनीतिक संदेश। आयोजक, चाहे जिस भी मंशा से आगे बड़े हों, इस मस्जिद का नाम “बाबरी-स्टाइल” रखकर उन्होंने एक ऐसा शब्द चुना है जो भारतीय राजनीति में सबसे धधकते प्रतीकों में से एक है। क्या इसका उद्देश्य किसी ऐतिहासिक दर्द को सांत्वना देना है? या फिर किसी विशेष वर्ग को संदेश देना? या यह चुनावी मनोविज्ञान का एक सुविचारित प्रयोग है? संपादकीय नज़र से देखें तो यह कदम आस्था से अधिक राजनीतिक प्रतीक-निर्माण की दिशा में दिखाई देता है।

चौथा पहलू—समुदाय और सामाजिक प्रभाव। मुर्शिदाबाद सदियों से साझा संस्कृति, सूफी परंपरा और शांत सामाजिक सह-अस्तित्व का क्षेत्र रहा है। ऐसे में, इतनी बड़ी धार्मिक परियोजना यदि बिना सामाजिक संवाद, सर्व-सम्मति और प्रशासनिक पारदर्शिता के आगे बढ़ती है, तो इसकी प्रतिध्वनि लंबे समय तक महसूस की जाएगी। धर्म के नाम पर शुरू की गई किसी भी पहल को तब ही सफल कहा जाएगा जब वह समुदाय में विश्वास, जवाबदेही और समावेश को बढ़ाए—न कि केवल भीड़, जोश और प्रतीकात्मकता को।

अंततः—यह सवाल सबसे बड़ा है कि क्या मुर्शिदाबाद को एक ऐसी विशाल मस्जिद की जरूरत थी, जिसका राजनीतिक अर्थ धार्मिक आवश्यकता से अधिक भारी हो? या फिर यह उन परियोजनाओं में से एक है, जो जनता की भावनाओं से ज्यादा उसके धैर्य और विवेक की परीक्षा लेती हैं?

हमारा निष्कर्ष सधा हुआ है: मस्जिद बनना आस्था का अधिकार है—लेकिन पारदर्शिता जनता का अधिकार है। और जब भूमि, धन, अनुमति, बजट और उद्देश्य पर इतने प्रश्न खड़े हों, तब किसी भी परियोजना—चाहे वह धार्मिक हो या विकासात्मक—को पारदर्शी प्रक्रियाओं से गुजरना ही होगा।

मुर्शिदाबाद की यह “नई बाबरी” न सिर्फ एक इमारत होगी—बल्कि यह तय करेगी कि भावनाएँ भारी पड़ेंगी या जवाबदेही।

नई दिल्ली | अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल पर केस दर्ज

FIR on Jai Anmol Ambani: अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल पर केस दर्ज, 228 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप

● NEWS AGENCY

नई दिल्ली: मशहूर कारोबारी अनिल अंबानी के बाद अब उनके बेटे जय अनमोल अंबानी पर भी सीबीआई का शिकंजा कस गया है। सीबीआई ने जय अनमोल अनिल अंबानी के खिलाफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) से जुड़े 228.06 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज किया है। यह मामला रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) से भी जुड़ा है।

सीबीआई ने मंगलवार को बताया कि यह मामला सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को हुए 228 करोड़ रुपये के वित्तीय नुकसान से संबंधित है। यह शिकायत बैंक की ओर से दर्ज कराई गई थी। इस शिकायत में आरएचएफएल, जय अनमोल अनिल अंबानी और रवींद्र शरद सुधाकर को निशाना बनाया गया है, जो दोनों कंपनी के निदेशक रह चुके हैं।



लोन का गलत इस्तेमाल बैंक की शिकायत के अनुसार आरएचएफएल ने अपने मुंबई स्थित ब्रांच से बिजनेस के लिए 450 करोड़ रुपये का लोन लिया था। बैंक ने कंपनी से कहा था कि वे पैसों का सही इस्तेमाल करें, समय पर ईएमआई भरें, ब्याज और दूसरे

चार्ज चुकाएं, सिक्वोरिटी डॉक्यूमेंट्स समय पर जमा करें और सारी बिक्री का पैसा बैंक खाते से ही निकालें। लेकिन कंपनी इन शर्तों का पालन नहीं कर पाई। इसके चलते 30 सितंबर 2019 को उनका लोन अकाउंट नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) यानी खराब लोन की

श्रेणी में आ गया।

कैसे खुला धोखाधड़ी का राज? ग्रांट थॉर्नटन (जीटी) नाम की कंपनी ने अप्रैल 2016 से जून 2019 तक की अवधि का फॉरेंसिक ऑडिट किया। इस ऑडिट में पता चला कि लोन के

पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ है, यानी पैसों को कहीं और ही लगाया गया। बैंक ने आरोप लगाया है कि कंपनी के पूर्व प्रमोटरों/निदेशकों ने खातों में हेरफेर करके और आपराधिक विश्वासघात करके धोखाधड़ी से पैसों का गबन किया। उन्होंने लोन के पैसे को उस मकसद के अलावा किसी और काम के लिए इस्तेमाल किया, जिसके लिए उन्हें यह लोन दिया गया था।

अनिल अंबानी की संपत्ति जब्त कथित लोन धोखाधड़ी मामले में अनिल अंबानी पर भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिकंजा कसा हुआ है। ईडी ने हाल ही में अनिल अंबानी ग्रुप की 1120 करोड़ रुपये की नई संपत्तियां जब्त की हैं। कुछ समय पहले भी ईडी ने 1452 करोड़ रुपये और 7500 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की थीं। यह मामला रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) और यस बैंक से जुड़ी कथित धोखाधड़ी का है।

टाटा के इस मल्टीबैगर शेयर ने निवेशकों को दिया ₹1 लाख करोड़ का झटका, क्या आपके पास है?

टाटा के इस मल्टीबैगर शेयर ने निवेशकों को दिया ₹1 लाख करोड़ का झटका,



स्टोर्स की संख्या

बर्नस्टीन के एनालिस्ट जिग्रांशु गोर ने कहा कि स्टोर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ना बिक्री बढ़ने की रफ्तार को धीमा करने का एक बड़ा कारण लगता है। उन्होंने बताया कि ट्रेट के विस्तार की रणनीति में यह एक बड़ी गलती थी। मार्च 2024 से Zudio ने 285 नए स्टोर खोले हैं। इससे उसके कुल स्टोर्स की संख्या 539 से बढ़कर 824 हो गई है। लेकिन इस तेजी से विस्तार की कीमत चुकानी पड़ी है। अब Zudio के 58% पुराने स्टोर्स को उसी शहर में खुले नए Zudio स्टोर से मुकाबला करना पड़ रहा है

गोल्डमैन सैश का अनुमान है कि Zudio की बाजार हिस्सेदारी अभी 1.5% है जो भविष्य में बढ़कर 5% हो जाएगी। उनका मानना है कि ज्यादातर नए प्रतिस्पर्धियों के पास अभी मजबूत स्टोर इकोनॉमिक्स नहीं हैं।

Zudio की लागत कम रखने की क्षमता उसे एक मजबूत स्थिति देती है। हाल के वित्तीय नतीजे मिले-जुले संकेत दे रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में, ट्रेट का रेवेन्यू पिछले साल की तुलना में 15.9% बढ़कर 4,818 करोड़ रुपये हो गया। यह बढ़ोतरी Westside और Zudio के संयुक्त 20.9% राजस्व वृद्धि से हुई, जो 3,939 करोड़ रुपये रहा।

टारगेट प्राइस

गोल्डमैन सैश ने कंपनी को न्यूट्रल रेटिंग दी है और 12 महीने का लक्ष्य 4,920 रुपये रखा है। बर्नस्टीन ने ट्रेट को आउटपरफॉर्म रेटिंग दी है और अपना लक्ष्य बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया है। इसी तरह एक्सिस सिक्वोरिटीज ने अपना लक्ष्य 6,160 रुपये से घटाकर 5,100 रुपये कर दिया है। वहीं, सिटी ने ट्रेट के शेयरों को 'सेल' रेटिंग दी है और लक्ष्य 4,350 रुपये रखा है।

सब खत्म हो गया... बशर-अल-असद को छोड़ कैसे भागी थी ईरानी सेना, जानें 'सीरिया के पतन' की कहानी

NEWS AGENCY

दमिश्क: सीरिया में बशर-अल-असद का तख्तापलट हुए एक साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर पूरे सीरिया में जश्न मनाया गया। सबसे बड़ा आयोजन राजधानी दमिश्क में किया गया, जहां पूर्व अल कायदा आतंकी से राष्ट्रपति बने अहमद अल-शरा ने मिलिट्री परेड की सलामी ली। लेकिन, सीरिया में असद सरकार का पतन अचानक नहीं हुआ। सीरियाई गृह युद्ध की शुरुआत 211 में लोकतंत्र के समर्थन में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर सरकार के बेरहमी से दमन के बाद शुरू हुआ। इसमें ईरान की भी बड़ी भूमिका रही, लेकिन वह असद की सत्ता के आखिरी वक्त में काम नहीं आया और उसकी सेना सीरिया छोड़कर भाग गई। इस कारण असद की सत्ता पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया और उन्हें रूस में शरण लेनी पड़ी।

ईरान, असद सरकार के दौरान सीरिया का सबसे बड़ा समर्थक था। उसने असद को अपने मिलिट्री एडवाइजर और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की फौज भेजी थी। इसके अलावा लेबनान के हिजबुल्लाह और इराक की मिलिशिया भी असद के समर्थन में थी। लेकिन, जब इस्लामिस्ट लीडरशिप वाली फोर्स के राजधानी दमिश्क की ओर तेजी से बढ़ते हमले के सामने वे हार गए। सीरियाई सेना के अधिकारियों और सैनिकों ने ईरानी सेना के अंदर काम किया, जिनका असर लड़ाई के दौरान असद की शक्ति कम होने के साथ बढ़ता गया।

बशर-अल-असद को छोड़ कैसे भागी थी ईरानी सेना



ईरानी अधिकारियों ने सीरिया को बीच में छोड़ा | रिपोर्ट के अनुसार, दमिश्क में सिक्खोरिटी हेडक्वार्टर में तैनात एक पूर्व सीरियाई सैन्य अधिकारी ने बताया कि पिछले साल 5 दिसंबर को उनके ईरानी अधिकारी ने उन्हें जरूरी मुद्दे पर बात करने के लिए माजेह जिले में एक ऑपरेशनल सेंटर में बुलाया। उस सैन्य अधिकारी ने कहा कि इस बैठक में 20 सीरियाई ऑफिसर और सैन्य अधिकारी शामिल थे। इनके सामने ईरानी सेना के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि "आज से, सीरिया में ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स नहीं रहेंगे। हम जा रहे हैं।" उन्होंने कहा, "सब खत्म हो गया है। आज से, हम आपके लिए जिम्मेदार नहीं हैं।" सीरियाई अधिकारी ने बताया कि उन्हें सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स को जलाने या नष्ट करने और कंप्यूटर से हार्ड ड्राइव निकालने का ऑर्डर दिया गया था।

दमिश्क पर कैसे हुआ विद्रोहियों का कब्जा

ईरानी सेना की वापसी के साथ ही सीरियाई सेना नेतृत्व विहीन हो गई। इस दौरान इस्लामी सेनाएं तेजी से आगे बढ़ रही थीं। उन्हें स्थानीय लोगों का समर्थन हासिल था, जो असर की सत्ता से तंग आ चुके थे। इस बीच असद सरकार ने सीरियाई सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए एक महीने की एडवांस सैलरी दे दी। इससे कई सैनिक पहले ही युद्ध छोड़कर भाग गए। इस्लामी सेनाओं की बढ़त और सैनिकों की घटती संख्या को देख बशर-अल-असद भी सीरिया छोड़कर रूस भाग गए और दमिश्क पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया।

सीरिया से लेबनान भाग गए थे ईरानी अधिकारी, ईरानी सेना और अधिकारियों को भागने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने जो मिला उसे समेटा और काफी कुछ छोड़कर वहां से निकल गए। 5 दिसंबर की शाम तक ईरानी कॉन्सुलेट खाली हो गया था।

WORLD NEWS | भारत से मिला साथ तो तालिबान ने पलट दी बाजी

भारत से मिला साथ तो तालिबान ने पलट दी बाजी, अफगानिस्तान ने खत्म की पाकिस्तान पर से निर्भरता, 'आर्थिक स्ट्राइक' से सदमे में शहबाज

काबुल | अफगानिस्तान ने कारोबार के लिए पाकिस्तान पर निर्भरता कम कर दी है। पाकिस्तान, बार बार बॉर्डर बंद कर ब्लैकमेल कर रहा था, जिसके बाद तालिबान ने पाकिस्तान पर अपनी निर्भरता घटाने की कोशिशें शुरू कर दी थी। इससे दोनों देशों के बीच का कारोबार भी काफी कम हो गया है। तोर्खम और चमन जैसे बड़े बॉर्डर क्रॉसिंग, जहां से पहले अफगानिस्तान के आधिकारिक कारोबार का करीब 40 फीसदी कारोबार होता था, वो 2024 के आखिर से 2025 में इस साल ज्यादातर समय बंद रहे हैं।

पाकिस्तान बात बात पर बॉर्डर क्रॉसिंग बंद कर रहा था और कई हफ्तों तक सीमा को बंद रखा जाता था। जिससे सब्जियां और दूसरी खराब होने वाली वस्तुओं का भारी नुकसान हो रहा था। अफगानिस्तान का सूखे मेवे के कारोबारियों को हर महीने करीब 200 मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा था। इसके अलावा अफगानिस्तान को तेल, गेहूं और दवाइयों मंगाने में भी काफी देरी का सामना करना पड़ता था। जिसके बाद अब तालिबान ने ईरान में भारत के बनाए चाबहार पोर्ट से कारोबार शुरू कर दिया है।



अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दिया जोर का झटका तालिबान ने भारत और नए हवाई संपर्कों के साथ-साथ उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कज़ाकिस्तान के साथ जमीनी कनेक्शन बढ़ाने सहित दूसरे रास्तों को ज्यादा प्राथमिकता दी है, जिसका मकसद एक ज्यादा मजबूत, मल्टीपोलर ट्रेड नेटवर्क बनाना है, जिसपर पाकिस्तान का प्रभाव ना हो। अक्टूबर 2025 में हुई झड़पों के बाद पाकिस्तान ने दोनों बॉर्डर क्रॉसिंग को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया है, जिसकी वजह से जहां दोनों देशों के बीच का कोराबार 2.5 अरब डॉलर से 3 अरब डॉलर के बीच था, वो अब गिरकर 1 अरब डॉलर से नीचे जा चुका है।

अफगान कृषि उत्पादों के दाम

पाकिस्तान में काफी ज्यादा बढ़ गये हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बॉर्डर बंद कर पाकिस्तान की दबाव बनाने की नीति नाकाम हो गई है और इससे उसने अफगानिस्तान पर अपनी आर्थिक पकड़ को काफी कमजोर कर लिया है। अफगान अब अपने कारोबार के लिए ईरान स्थित चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे भारत ने डेवलप किया है। 2018 से संचालित यह पोर्ट अफगानिस्तान को पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए सीधे भारतीय बाजारों तक पहुंच देता है। 2022 के बाद से यहां से 1.5 मिलियन टन भारतीय गेहूं और दालें अफगानिस्तान भेजी जा चुकी हैं, जबकि अफगान अनार और किशमिश अब भारतीय शहरों तक कुछ ही दिनों में पहुंचने लगे हैं।

तालिबान ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका नवंबर 2025 में भारतीय यात्रा के दौरान अफगान अधिकारियों ने वीजा में आसानी, हवाई कारोबार शुल्क को कम करने और नई कार्गो उड़ानों पर समझौते आगे बढ़ाए। दूसरी तरफ उत्तरी मार्ग, जैसे उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाखस्तान के जरिए भी अब अफगानिस्तान कारोबार में तेजी जा ला रहा है। हैरातन रेल टर्मिनल और तेरमेज ब्रिज के रास्ते अफगानिस्तान का उज़्बेकिस्तान के साथ व्यापार 1.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है और 2025 में 2 बिलियन डॉलर के कारोबार का लक्ष्य रखा गया है।

Trump Tariff Threat | ट्रंप की चावल पर जोर आजमाइश बेकार

Trump Tariff Threat: ट्रंप की चावल पर जोर आजमाइश बेकार, भारत पर रत्ती भर नहीं फर्क, फिर गलत जगह हाथ डाल दिया क्या?

नई दिल्ली | भारतीय चावल निर्यातकों ने अमेरिका की ओर से अतिरिक्त टैरिफ लगाने की आशंका को ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। उनका कहना है कि मांग पहले की तरह ही बनी हुई है। अमेरिका को होने वाले निर्यात की कम मात्रा को देखते हुए इस क्षेत्र पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। भारतीय चावल निर्यातक महासंघ (IREF) के अध्यक्ष प्रेम गर्ग ने बताया कि अमेरिका को बासमती चावल का निर्यात देश के कुल 60 लाख टन सालाना निर्यात का तीन फीसदी से भी कम है। वहीं, भारत के कुल चावल निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी एक फीसदी से भी कम है।

यह बयान तब आया है जब ट्रंप ने अमेरिकी कृषि सब्सिडी पर चर्चा के दौरान भारतीय चावल पर नए टैरिफ की चेतावनी दी है। व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की धमकी किसी बड़े नीतिगत बदलाव का संकेत कम, बल्कि राजनीतिक बयानबाजी ज्यादा है। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने भी कहा है कि ट्रंप की धमकी राजनीति है, नीति नहीं।



अमेरिका को ही झेलना होगा दर्द

निर्यातकों का कहना है कि अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाता भी है तो इसका असर अमेरिकी खरीदारों पर पड़ेगा, न कि भारतीय व्यापार पर। आईआरआईएफ के अध्यक्ष प्रेम गर्ग ने

कहा, 'हमारे कुल चावल निर्यात में अमेरिकी बाजार का बड़ा हिस्सा नहीं है। दूसरे नए बाजार भी लगातार बढ़ रहे हैं।' उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों के भारत पर चावल 'डंपिंग' के आरोपों को 'पूरी तरह गलत' बताया।

गर्ग के अनुसार, अमेरिका सालाना केवल लगभग 27 लाख टन भारतीय चावल का आयात करता है, जो भारत की वैश्विक उपस्थिति की तुलना में बहुत कम है। यह बयान ऐसे समय आया है जब वाशिंगटन में भारतीय चावल पर अतिरिक्त शुल्क लगाने पर चर्चा चल रही है। इस पर पहले से ही 50 फीसदी टैरिफ लगा हुआ है।

टैरिफ का मांग पर कोई असर नहीं

गर्ग ने बताया कि छह महीने पहले 10 फीसदी से शुरू हुआ टैरिफ पिछले तीन महीनों में बढ़कर 25 फीसदी और फिर 50 फीसदी हो गया। लेकिन, इसका मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा, 'नवंबर में निर्यात पिछले साल जैसा ही है।'

उद्योग के जानकारों का मानना है कि किसी भी और शुल्क बढ़ोतरी का बोझ मुख्य रूप से अमेरिकी उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगा। राइसविला ग्रुप के सीईओ सूरज अग्रवाल ने कहा कि अमेरिका को निर्यात की जाने वाले भारतीय बासमती और प्रीमियम गैर-बासमती चावल की किस्में एशियाई और पश्चिमी एशियाई समुदायों के लिए एक मुख्य भोजन हैं। उन्होंने कहा, 'ये जरूरत की चीजें हैं, विलासिता के सामान नहीं। मांग पर असर नगण्य होगा। किसी भी अतिरिक्त टैरिफ का बोझ केवल अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।'

चीनी J-10 के बाद यूरोफाइटर टाइफून लड़ाकू विमान खरीदेगा बांग्लादेश, इटली के साथ की बड़ी डील

ढाका: बांग्लादेशी वायुसेना ने यूरोफाइटर टाइफून लड़ाकू विमान खरीदने के लिए इटली की डिफेंस कंपनी लियोनार्डो के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) साइन किया है। इसके तहत बांग्लादेश ने इटली को यूरोफाइटर टाइफून खरीदने की अपनी इच्छा को जताया है। हालांकि, इस समझौते को अभी धरातल पर उतरने के लिए लंबा सफर करना बाकी है। इसके बावजूद, इसे बांग्लादेशी वायुसेना के मॉडर्नाइजेशन में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बांग्लादेश इससे पहले चीन के J-10 लड़ाकू विमान में भी अपनी दिलचस्पी दिखा चुका है।

वायुसेना मुख्यालय में समझौते पर हुआ हस्ताक्षर बांग्लादेशी वायुसेना के वेरिफाइड फेसबुक पेज के मुताबिक, LOI पर 9 दिसंबर को ढाका में वायुसेना मुख्यालय में साइन किए गए। इस कार्यक्रम में बांग्लादेशी वायुसेना के चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान और बांग्लादेश में इटली के एम्बेसडर एंटोनियो एलेसेंड्रो मौजूद थे। साइनिंग सेरेमनी में आर्म्ड फोर्स डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर और इटैलियन साइड के रिप्रेजेंटेटिव समेत सीनियर ऑफिशियल भी मौजूद थे।

वायुसेना को अपग्रेड कर रहा बांग्लादेश | वायुसेना के मुताबिक, इस एग्रीमेंट में यूरोफाइटर टाइफून जेट की सफ़लाई शामिल है, जिनके BAF के अगली पीढ़ी के मल्टी-रोल कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ के हिस्से के तौर पर उसके फ्रंटलाइन फ्लीट में शामिल होने की उम्मीद है। यह बांग्लादेश की वायुसेना को मल्टीरोल कॉम्बैट फाइटर जेट्स के साथ मॉडर्नाइज करने के चल रहे प्लान का हिस्सा है।





नांदेड़वासियों का इंतज़ार खत्म! 25 दिसंबर से नांदेड़-मुंबई फ्लाइट सेवाएं शुरू

नांदेड़ — लंबे इंतज़ार के बाद नांदेड़ से मुंबई के लिए सीधी हवाई सेवा आखिरकार शुरू होने जा रही है। स्टार एयर ने घोषणा की है कि 25 दिसंबर से नांदेड़-मुंबई फ्लाइट टेक ऑफ करेगी। एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट पर टिकट बुकिंग भी शुरू हो गई है, जिससे यात्रियों में उत्साह का माहौल है।

फिलहाल स्टार एयर नांदेड़ से बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे और दिल्ली के लिए उड़ानें संचालित करती है। लेकिन नांदेड़ के लोगों की सबसे अधिक मांग मुंबई फ्लाइट को लेकर थी। इस सेवा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद अशोक चव्हाण ने कई बार मंत्रालय स्तर पर पहल की थी। नवंबर में उड़ान शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन तकनीकी

कारणों से देरी हुई। नई सेवा शुरू होने से नांदेड़ समेत हिंगोली, परभणी, यवतमाल, लातूर और वाशिम जैसे जिलों के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही अमृतसर के लिए हवाई सेवा शुरू करने की मांग भी बढ़ रही है, जबकि गोवा के लिए उड़ान शुरू होने में अभी समय लग सकता है। शुरुआती दिनों में नांदेड़-मुंबई फ्लाइट सप्ताह में तीन दिन — मंगलवार, गुरुवार और शनिवार — उपलब्ध होगी। बाद में इसे पूरे सप्ताह के लिए बढ़ाया जा सकता है। पहले भी नांदेड़-मुंबई उड़ान को अच्छा प्रतिसाद मिला था, और अब इसके दोबारा शुरू होने से मुंबई और अन्य महानगरों तक पहुंच और अधिक आसान हो जाएगी।

ZP NANDED | नशे में धुत शिक्षक का डांस वीडियो वायरल, ZP ने किया तुरंत निलंबित

नांदेड़: स्कूल में नशे में धुत शिक्षक का डांस वीडियो वायरल, ZP प्रशासन ने किया तत्काल निलंबन

● मोहम्मद शाकेर अहमद

नांदेड़ जिले में एक शर्मनाक और चिंताजनक घटना सामने आई है, जिसने शिक्षा विभाग से लेकर अभिभावकों तक सभी को हैरान कर दिया है। माहुर तालुका के शेकापुर गांव के ZP प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक अनंत रामचरण वर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वे कक्षा के अंदर नशे में धुत होकर लड़खड़ाते हुए डांस करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में बच्चे भी मौजूद थे, जिसके चलते अभिभावकों में भारी नाराज़गी फैल गई। वीडियो सामने आने के



तुरंत बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने मामले की तत्काल जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में पुष्टि हुई कि शिक्षक ड्यूटी के समय शराब के नशे में थे और छात्रों के सामने

अनुशासनहीन व्यवहार कर रहे थे। घटना की गंभीरता देखते हुए ज़िला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मेघना कवळी ने महाराष्ट्र ZP सेवा (आचरण) नियम 1967

के तहत शिक्षक अनंत वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें ZP प्राथमिक शिक्षा विभाग के

मुख्यालय में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है।

अभिभावकों का कहना है कि स्कूल बच्चों के सीखने और सुरक्षित माहौल का स्थान होता है, जहाँ इस तरह की हरकतें बिल्कुल अस्वीकार्य हैं। स्थानीय लोगों में भी रोष है और वे ऐसे शिक्षकों पर कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर सख्त कदम उठाए जाते रहेंगे, ताकि स्कूलों में अनुशासन और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

नांदेड़: बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने पर 22 वाहनों पर कार्रवाई, परिवहन अधिकारी का चेतावनी संदेश



नांदेड़ शहर में बिना नंबर प्लेट वाले हाईवा और टिपर वाहनों के चलने की जानकारी मिलने पर प्रादेशिक परिवहन कार्यालय ने 7 से 8 दिसंबर 2025 के बीच विशेष जांच अभियान चलाया। इस अभियान में कुल 184 वाहनों की जांच की गई, जिसमें 22 वाहनों पर नंबर प्लेट न होने और मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की गई। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने जिले के सभी वाहनधारकों से अपील की है कि वाहन पर नंबर प्लेट लगाकर ही सड़क पर चलाएँ, अन्यथा कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होगी।

बिहार | 'मुस्लिम वोट बंटने से Mahagathbandhan को बड़ा झटका

बिहार चुनाव 2025: AIMIM बोली – 'मुस्लिम वोट बंटने से Mahagathbandhan को बड़ा झटका

मुंबई | बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के बाद AIMIM ने दावा किया है कि राज्य में मुस्लिम समुदाय के वोटों के बंटने के कारण महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा कि मुस्लिम मतदाता अगर एकजुट रहे होते तो परिणाम पूरी तरह अलग होता। उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि RJD और Congress ने जानबूझकर मुस्लिम वोटों को बाँटकर महागठबंधन को कमजोर किया।

विजय के आंकड़ों में देखा गया है कि AIMIM ने सीमांचल क्षेत्र की कई मुस्लिम बहुल सीटों पर जोरदार चुनाव प्रचार किया। 243 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए ने 202 की सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि महागठबंधन मात्र 34 सीटों तक सिमट गया।



विशेषज्ञों के अनुसार इस बार यह बदलाव विशेष रूप से उस क्षेत्र में देखने को मिला जहाँ मुस्लिम आबादी घनी है — सीमांचल (किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार आदि) — जहाँ मुस्लिम मतदाता अब पारंपरिक दलों से हट कर AIMIM पर झुके। चुनाव परिणामों में इसका असर साफ दिखा: 243 सीटों वाली

विधानसभा में कुल मुस्लिम विधायकों की संख्या घटकर मात्र 11 रह गई, जबकि 2020 में यह संख्या 19 थी। उन 11 में से 5 विधायक AIMIM के बने, जबकि शेष आरजेडी, कांग्रेस और अन्य दलों से हैं। AIMIM का कहना है कि महागठबंधन ने उन्हें गठबंधन में शामिल करने का प्रस्ताव दिया था,

लेकिन RJD-कांग्रेस ने “B-टीम” कहकर उन्हें खारिज कर दिया। इसके बावजूद AIMIM ने सीमांचल में अपना प्रभाव दिखाया और 29 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस वोट बंटवारे ने महागठबंधन को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया, क्योंकि पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक इस बार टूट गया। कई मुस्लिम मतदाताओं ने अब धार्मिक पहचान के बजाय प्रतिनिधित्व, आकांक्षाओं और स्थानीय मुद्दों को आधार बनाकर वोट दिया। अब सवाल उठता है — क्या आगामी समय में मुस्लिम मतदाताओं की यह एकता बनी रहेगी, या फिर मजबूती से अलग-अलग दलों में बंटाव जारी रहेगा?



नांदेड़ मनपा में ई-ऑफिस प्रणाली के लिए 2 करोड़ का कंप्यूटर सामान खरीदा, कामकाज होगा 100% ऑनलाइन

नांदेड़ : नांदेड़-वाघाला शहर महानगरपालिका अब पूरी तरह पेपरलेस होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। मनपा प्रशासन ने ई-ऑफिस प्रणाली को सक्षम बनाने के लिए लगभग 1 करोड़ 99 लाख 42 हजार रुपये खर्च कर 200 कंप्यूटर, 100 प्रिंटर, 25 स्कैनर और 25 लैपटॉप खरीदे हैं। यह सामग्री मनपा के निधि से नाशिक स्थित श्रद्धा इंटरप्राइजेस से शासन के GeM पोर्टल के माध्यम से मंगाई गई है। सामान मनपा कार्यालय में उपलब्ध हो गया है और आने वाले दिनों में 100% ऑनलाइन ई-ऑफिस

प्रणाली शुरू की जाएगी। मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे के मार्गदर्शन में मुख्य प्रशासकीय कार्यालय, छह क्षेत्रीय कार्यालयों सहित अन्य विभागों में ई-ऑफिस व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया तेज की गई है। अभी कुछ विभाग सीमित स्तर पर ऑनलाइन सेवाएँ दे रहे हैं, लेकिन पुरानी कंप्यूटर प्रणाली के कारण कामकाज प्रभावित हो रहा था। नए उपकरणों से अब प्रशासनिक कार्य और अधिक गति पकड़ेंगे।

ई-ऑफिस व्यवस्था लागू

होने के बाद फाइलें दडवाकर रखने वालों और कामचोरी करने वाले कर्मचारियों की पोल भी खुलने की पूरी संभावना है, क्योंकि सभी विभागों का कामकाज पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से दर्ज होगा। विशेष रूप से गुठेवारी विभाग में अब तक कंप्यूटर प्रणाली का पर्याप्त उपयोग नहीं हो रहा था, जिससे कामकाज में अड़चनें आती थीं। नई व्यवस्था से ऐसे सभी अड़थकलों पर लगाम लग सकेगी और मनपा की कार्यक्षमता में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है।

नांदेड़ में 35 लाख की बॅग लिफ्टिंग... 24 घंटे बाद भी आरोपी फरार

नांदेड़ | शहर के सबसे व्यस्त जुना मोंढा इलाके में व्यापारी की 35 लाख रुपये की बॅग उड़ा ले जाने वाले आरोपी 24 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। सीसीटीवी फुटेज में आरोपियों के चेहरे स्पष्ट दिखाई देने के बावजूद अब तक उन्हें पकड़ा न जाना, कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

घटना सोमवार रात करीब 9:30 बजे की है। जुना मोंढा के व्यापारी पारसेवार अपने कर्मचारी के साथ दुकान बंद कर कार से घर लौट रहे थे। रास्ते में गाड़ी के पिछले टायर में हवा कम दिखने पर दोनों नीचे उतरकर चेक कर रहे थे। इसी बीच दुचाकी से आए दो युवक कार की फ्रंट सीट पर रखी बॅग लेकर फरार हो गए।

बॅग में करीब 30 लाख रुपये नकद होने की जानकारी सामने आई है। आसपास के दुकानों के सीसीटीवी में यह वारदात कैद हुई है। फुटेज में दिख रहा है कि आरोपियों ने घटना से पहले भी काफी देर तक इलाके में चक्कर लगाए थे, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि इस वारदात में दो से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं।